

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प - उज्जैन  
प्रकरण क्रमांक - 2013-14 पुनरीक्षण

(16)

समंदरसिंह आयु 62 वर्ष पिता दुलेसिंहजी जाति राजपूत  
निवासी ग्राम - असावता तहसील बड़नगर जि.उज्जैन  
आवेदक  
विरुद्ध

01. महिला कमलाबाई पति रामसिंहजी पिता थावरजी  
जाति बलाई, धंधा कृषि, निवासी ग्राम - असावता  
तहसील बड़नगर जिला उज्जैन म0प्र0
02. राजपालसिंह आयु 28 वर्ष पिता समंदरसिंहजी  
जाति राजपूत, निवासी ग्राम असावता तह.बड़नगर
03. जातु पिता समंदरसिंहजी आयु 20 वर्ष  
जाति राजपूत, निवासी ग्राम - असावता तह.बड़नगर  
अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा - 50 म.प्र. भूरासं

न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील बड़नगर  
द्वारा प्रकरण क्रमांक - 12-अ-13/10-11 मे पारित  
आदेश दिनांक - 19/12/2013 से असंतुश्ट होकर -  
पुनरीक्षण याचिका।

मान्यवर महोदय,

है :-

आवेदक की और से पुनरीक्षण याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत

### प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि अनावेदक कमलाबाई द्वारा धारा 131 भूरासं का  
आवेदन प्रस्तुत किया गया। अनावेदक की और से धारा 32 भूरासं का जवाब  
प्रस्तुत होकर आवेदन निरस्त हुआ। अनावेदक द्वारा मूल आवेदन पत्र धारा 131  
का जवाब तैयार कर अभिभाषक महोदय की फाईल मे रखा गया परन्तु भुलवश  
प्रस्तुत नहीं हो सका। प्रकरण मे साक्ष्य की तैयारी के समय उक्त त्रुटी का  
ज्ञान होने पूरे दिनांक 19/12/13 को मूल आवेदन पत्र का जवाब धारा 32  
भूरासं के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने  
अभिलेख पर नहीं लिया तथा धारा 32 भूरासं का आवेदन पत्र का निराकरण

LX(a)BR(H)-11 t.

भूजस्व मण्डल, अध्यप्रदेश, ग्वालियर

(27)

प्रकरण क्रमांक — निरा. 760-एक / 14

जिला — उज्जैन

संपर्क संख्या दर्तक	भूजस्व आदेश वाली विवरण	प्रकरण संख्या एवं अधिकारी का नाम हस्ताक्षर
------------------------	---------------------------	--

2-4-14

प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 29 घेशियाँ ही जाने के अधिकार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब को अभिलेख पर लेना समव नहीं माना है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि प्रकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में प्रचलनशील है अतः जबाब को रिकार्ड पर लेना न्याय की दृष्टि से उचित होगा। अतः उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मजबू जाए। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

प्रश्नां सदस्य